चुनाव आयोग

चुनाव

- आम चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किया जाता है।
- प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, चुनाव में वोट देने का हकदार है, बशर्ते वह कानून द्वारा अयोग्य न हो।
- संसद या राज्य के विधानमंडल के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय में अपील के साथ ही उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका द्वारा विचाराधीन कहा जा सकता है। (अनुच्छेद 329)
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए विशेष मंच सर्वोच्च न्यायालय है (अनुच्छेद 71)

चुनाव आयोग

- चुनाव के लिए और कुछ अन्य सहायक मामलों के लिए पूरी प्रक्रिया और मशीनरी की निगरानी के लिए, संविधान इस स्वतंत्र निकाय के लिए प्रावधान करता है (अनुच्छेद 324).
- निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है।
- चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।
- राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं (अनुच्छेद 324(2)].

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)

- राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- सीईसी को समान दर्जा प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को समान वेतन और भत्ते मिलते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके कार्यालय से केवल एक तरीके से और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित आधार से हटाया जा सकता है.
- अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- चुनाव आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के अधीक्षण, निर्देशन और आचरण की शक्ति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव हैं (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 324(1).
- चुनाव आयोग की सहायता के लिए चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है (सन्दर्भ.: अनुच्छेद. 324(4),

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

Sl.	नाम	अवधि
1.	सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 – 19 दिसम्बर., 1958
2.	के वी सुंदरम	20 दिसम्बर., 1958 – 30 सितम्बर., 1967
3.	एस पी सेन वर्मा	01 अक्टूबर., 1967 – 30 सितम्बर., 1972
4.	डॉ नागेंद्र सिंह	01 अक्टूबर., 1972 – 06 फरवरी., 1973
5.	टी स्वामीनाथन	07 फरवरी., 1973 – 17 जून, 1977
6.	एस एल शकधर	18 जून, 1977 – 17 जून, 1982
7.	आर के त्रिवेदी	18 जून, 1982 – 31 दिसम्बर, 1985
8.	आर वी एस पेरी शास्त्री	01 जनवरी., 1986 – 25 नवम्बर., 1990
9.	श्रीमती वी एस राम देवी	26 नवम्बर., 1990 – 11 दिसम्बर., 1990
10.	टी एन शेषन	12 दिसम्बर., 1990 – 11 दिसम्बर., 1996
11.	एम एस गिल	12 दिसम्बर., 1996 – 13 जून, 2001
12.	जे एम लिंगदोह	14 जून, 2001 – 07 फरवरी., 2004
13.	टी एस कृष्ण मूर्ति	08 फरवरी., 2004 – 15 मई, 2005
14.	बी बी टंडन	16 मई, 2005 – 07 फरवरी., 2006
15.	एन गोपालस्वामी	08 फरवरी., 2006 – 19 अप्रैल, 2009
16.	नवीन चावला	20 अप्रैल, 2009 – 29 जुलाई, 2010
17.	एस वाई कुरैशी	30 जुलाई, 2010 – 10 जून, 2012
18.	वी. एस संपत	11 जून, 2012 – 15 जनवरी, 2015
19.	एच एस ब्रह्मा	16 जनवरी 2015 – 18 अप्रैल, 2015
20.	नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 – 05 जुलाई, 2017
21.	अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 – 22 जनवरी, 2018
22.	ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018- 1 दिसम्बर, 2018
23.	सुनील अरोड़ा	2 दिसम्बर, 2018 -

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य हैं:

1. प्रत्येक आम चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण।
2. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
3. विभिन्न राजनीतिक दलों की मान्यता और इन दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना.

2 दिसंबर, 2000 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 को चुनाव आयोग द्वारा 31 अगस्त 1968 को संविधान और और चुनाव नियम 1961 के संचालन के नियम 5 और 10 के 324 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में घोषित किया गया था। आदेश में प्रावधान किए गए, दोनों राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए और राष्ट्रीय और राज्य दलों के रूप में उनकी मान्यता के लिए और साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के विनिर्देश और आवंटन के लिए।

TEST SERIES
Bilingual
KVS PRT
30 TOTAL TESTS
Validity : 12 Months

आयोग ने निर्णय लिया है कि इसके बाद एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा

I. यदि यह किसी भी चार या अधिक राज्यों में मतदान के वैध वोटों में से कम से कम छह प्रतिशत (6%) हासिल करता है, तो आम लोगों के लिए, हाउस ऑफ़ पीपुल या राज्य विधान सभा के लिए, और

II. इसके अलावा, यह किसी भी राज्य या राज्यों के लोगों की सभा में कम से कम चार सीटें जीतता है। या, यह हाउस ऑफ पीपुल में कम से कम दो प्रतिशत (2%) सीटें जीतता है (यानी मौजूदा सदन में 11 सीटें 543 सदस्य हैं), और ये सदस्य कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से चुने जाते हैं.

एक राजनीतिक दल को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने का अधिकार होगा, यदि

(i) यह आम चुनाव में राज्य में प्रदत्त वैध मतों में से कम से कम छह प्रतिशत (6%) सुरक्षित करता है, या तो संबंधित लोगों की सभा या संबंधित राज्य की विधान सभा को; तथा

(ii) इसके अलावा, यह संबंधित राज्य की विधान सभा में कम से कम दो सीटें जीतता है। या, यह राज्य की विधान सभा की कुल सीटों में से कम से कम तीन प्रतिशत (3%) जीतता है, या विधानसभा की कम से कम तीन सीटें, जो भी अधिक हो.

4. राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता की तैयारी।
5. संसद के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में राष्ट्रपति को सलाह की निविदा आदि।
6. चुनाव व्यवस्था से संबंधित विवादों को देखने के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति।
7. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा केंद्रीय प्रसारण और टेलीकास्ट के लिए रोस्टर की तैयारी।
8. मतदाता सूचियों को हर समय अपडेट रखें।
9. मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना.

TEACHERS